माननीय श्री हरबंस सिंह राय, न्यायमूर्ति

निर्मल सिह-याचिकाकर्ता।

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़,-प्रतिवादी।

आपराधिक विविध. 1990 का नंबर 1541-एम.

6 जून 1990

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954-धारा. 9 और 20(1) - खाद्य निरीक्षकों को नमूने लेने और अभियोजन शुरू करने के लिए अधिकृत करने वाली अधिसूचना - मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना - ऐसी अधिसूचना की वैधता।

यह सभी प्रासंगिक समयों पर माना गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था और प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र सरकार है। नमूना लेने वाले खाद्य निरीक्षक को अधिनियम की धारा 9(1) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और अभियोजन अधिनियम की धारा 20(1) के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था।

(पैरा 6 एवं 8)

धारा 482 सीआर के तहत याचिका। पी. सी. प्रार्थना कर रहे हैं कि शिकायत परिशिष्ट पी-1 को रद्द करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए। कृपया अनुलग्नक पी-2 को भी रद्द किया जाए क्योंकि यह मुख्य प्रशासक, चंडीगढ़ द्वारा की गई अधिसूचना पर आधारित है जो खराब है और अनुपालन में नहीं है।

(7) 1966–1968 अनुपूरक पी.एल.आर. 415.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 20(1) के साथ, पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने और विवादित आदेश और शिकायत को रद्द करने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील डी. एस. मरवाहा।

प्रतिवादी की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनिध कश्यप, उनके साथ अधिवक्ता थे।

निर्णय

माननीय श्री हरबंस सिंह राय, न्यायमूर्ति - यह आदेश आपराधिक विविध का निपटान करेगा जिसका 1990 का नंबर 1541-एम और साथ ही आपराधिक विविध 1987 की संख्या 7086-

एम और 7841-एम, 2785-एम, 2786-एम, 2787-एम, 2788एम, 4065-एम। 1988 का 4877-एम, 6252-एम, 6664-एम, 7931-एम, 8355-एम और 8943-एम, 1989 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 601, सीआरएल। विविध. संख्या 732-एम, 109ओ-एम, 1801-एम, 2012-एम, 2831-एम, 3339-एम, 5260-एम, 5291-एम, 7717-एम, 8254-एम और 1989 और 807-एम एम, 1010-एम, 1842-एम, 1929-एम, 1995-एम, 2158-एम, 2631-एम, 2756-एम, 3214-एम, 3217-एम, 3371-एम, 3528-एम, 3588-एम, 1990 के 3537-एम, 3659-एम, 3904-एम, 4075-एम, 4119-एम और 4875-एम कानून के सामान्य प्रश्न इन सभी मामलों में शामिल हैं।

इन मामलों के तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें केवल कानूनी बिंदु शामिल हैं जिन्हें निम्नानुसार गिनाया गया है:

(i) क्या जिन खाद्य निरीक्षकों ने मिलावटी भोजन के नमूने लिए थे, उन्हें उचित सरकार द्वारा वैध रूप से नियुक्त नहीं किया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (बाद में इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9(i) के तहत।

(ii) क्या इंस्पेक्टर जिन्होंने अभियोजन स्थापित किया था। प्रत्येक मामले में, अधिनियम की धारा 20(i) के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए विधिवत अधिकृत नहीं किया गया था।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने 1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 3380 **पवन कुमार v चंडीगढ़ प्रशासन और दूसरा**, अपने तर्क के समर्थन में।

3. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड तथा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन किया है। अधिनियम की धारा 9(1) एवं 20(1) के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

"9. खाद्य निरीक्षक(1) केंद्र सरकार। या राज्य सरकार. सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे। ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक होने की निर्धारित योग्यता रखने वाले, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जा सकता है:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसका किसी खाद्य पदार्थ के निर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो, उसे इस धारा के तहत खाद्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

20. अपराधों का संज्ञान और मुकदमा- (1) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, जो धारा 14 या धारा 14-ए के तहत अपराध नहीं है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की लिखित सहमति के अलावा या उसके बिना शुरू नहीं किया जाएगा। या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति।

बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियोजन धारा 12 में निर्दिष्ट क्रेता (या मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ) द्वारा शुरू किया जा सकता है, यदि वह (या वह) शिकायत के साथ सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति अदालत में पेश करता है .

4. सभी मामलों में, नीचे उद्धृत अधिसूचना के समान अधिसूचनाएं जारी की गईं और प्रशासन राजपत्र में प्रकाशित की गईं:-

"चंडीगढ़ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना 9 फरवरी, 1984. संख्या MH-III-84/1425-के अभ्यास में द्वारा प्रदत्त शक्तियां खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (केंद्रीय अधिनियम क्रमांक 37, 1954) की धारा 9 की उपधारा (1) मुख्य आयुक्त I चंडीगढ़ का क्षेत्र के लिए खाद्य निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है संघ निम्नलिखित स्वच्छता निरीक्षकों को चंडीगढ़

1. श्री वीरेश्वरसिंह।

2. श्री एम.के. शर्मा

3. श्री बलबीरसिंह

पी.डी. वशिष्ट,

वित्त सचिव

चंडीगढ़ प्रशासन

अधिसूचना दिनांक 27-10-1979. क्रमांक 7632-एमएच-III-79/16991- चंडीगढ़ प्रशासन के अधिक्रमण में। स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2859-एमएच-III-78/9174 दिनांक 5 मई 1978 और खाद्य अपमिश्रण निवारण की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम, 1954 (1954 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37) मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकृत करते हुए प्रसन्न हैं संघक्षेत्रचंडीगढ़ के भीतर उपरोक्त अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करना :

1. श्री कुलदीपसिंहसेनेटरी इंस्पेक्टर चंडीगढ़ प्रशासन।

2. श्री हरदियालसिंहस्वच्छता निरीक्षकचंडीगढ़प्रशासन।

एसडी/- राम गोपाल,

वित्त सचिव,

चंडीगढ़ प्रशासन".

5. श्री आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, संघ क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए विद्वान वकील दलील दी गई है कि प्रत्येक मामले में नमूना संबंधित अधिसूचना में नामित खाद्य निरीक्षक द्वारा लिया

गया था और अदालत में अभियोजन उक्त अधिसूचना में नामित व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सभी प्रासंगिक समयों पर, संघ क्षेत्र के प्रशासक चंडीगढ़भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त को मुख्य आयुक्त कहा जाता था और वह संघ क्षेत्र चंडीगढ़ केंद्र सरकार है. उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में **जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897** की धारा 3(8)(iii) पर भरोसा जताया है। उन्होंने गोवा सैंपलिंग एसोसिएशन v पर भी भरोसा किया है। जनरल सुपरिटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड और अन्य, **AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 357** जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:-

"उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तीन अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का उल्लेख करने के बाद, जैसा कि यहां निर्धारित और चर्चा की गई है, पहली बार देखा कि परिभाषा को ध्यान से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन पृष्ठ 183 के संबंध में है। उसके तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करना **संविधान के अनुच्छेद 239** में केंद्र सरकार है। अभी तक कोई विवाद नहीं है. उच्च न्यायालय ने तब कहा कि उसे यह मानना होगा कि जहां तक संघ क्षेत्र की बात है तो प्रशासक राज्य सरकार है। का संबंध है और राज्य सरकार की परिभाषा में ऐसा प्रावधान किया गया है **सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(60)।** उच्च न्यायालय व्याख्या करने में त्रुटि में पड़ गया **धारा 3(60) का खंड (सी)** जो अपने वास्तविक निर्माण पर दिखाएगा कि संघ के संबंध में राज्य सरकार की अवधारणा ही इस परिभाषा से लुप्त हो गई है।" क्षेत्रसंघ, केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी। क्षेत्रसंघ वहां राज्य सरकार की कोई अवधारणा नहीं है लेकिन जहां भी `राज्य सरकार' अभिव्यक्ति का प्रयोग क्षेत्र

6. इस न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले की रिपोर्ट मुख्य आयुक्त, संघ क्षेत्र में दी गई है। चंडीगढ़और अन्य v। सुशील आटा, दाल एवं ऑयल मिल्स, **1983(2) इंडियन लॉ रिपोर्टर पेज 183** पर भी की ओर से भरोसा किया गया है। . क्षेत्रसंघ

7. गोवा सैंपलिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर, मुझे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में कोई बल नहीं मिला कि खाद्य निरीक्षक जिसने किसी भी मामले में नमूना लिया था अधिनियम की धारा 9(1) के तहत उचित सरकार द्वारा मामलों की नियुक्ति नहीं की गई थी और अधिनियम की धारा 20(1) के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा अभियोजन शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, मैं सभी याचिकाएं खारिज करता हूं।'

8. पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 15 जून 1980 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह : अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा